



लघु एवं सेवा कर (GST) का लघु उद्योगों की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव: एक समीक्षा

डॉ० मोहित भारद्वाज^{1*} और डॉ० पंकज यादव²

¹ असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, गन्ना उत्पादक महाविद्यालय, बहेड़ी, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

² प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

Correspondence Author: डॉ० मोहित भारद्वाज

Received 14 Sep 2025; Accepted 23 Oct 2025; Published 4 Nov 2025

DOI: <https://doi.org/10.64171/JSRD.4.4.42-47>

Abstract

इस शोध-पत्र का उद्देश्य भारत में लागू किए गए वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax — GST) का लघु उद्योगों (Micro and Small Enterprises / MSMEs) की वित्तीय स्थिति, नकदी प्रवाह (cash flow), अनुपालन बोझ (compliance burden), कर लाभ और बाजार-संरचना पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभावों का समेकित तथा समालोचनात्मक समीक्षा करना है। GST के लागू होने (1 जुलाई 2017) के बाद लघु उद्योगों पर प्रभाव बहुआयामी रहे हैं — एक ओर कर-वृद्धियों का समापन और इनपुट-क्रेडिट का लाभ मिलने से औद्योगिक एकीकरण और formalisation को बढ़ावा मिला; दूसरी ओर डिजिटल-निर्भर रिटर्न प्रक्रिया, इनवॉइस-मानचित्रण और कम्प्लायंस लागत ने छोटे उद्यमों पर देयता और नकदी-संकट उत्पन्न किये। कुछ अध्ययनों ने छोटे निर्यातक एवं परम्परागत सूक्ष्म इकाइयों में शुल्क-स्थगन और आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधानों का संकेत दिया है। इस पेपर में सरकारी स्रोतों (M/o MSME की वार्षिक रिपोर्टें), बहु-देशीय संस्थानों (World Bank) के विश्लेषणों और 2017–2025 के पारित साहित्य का समेकन प्रस्तुत किया गया है ताकि GST के लाभ-हानि, नीति-रिकॉमैण्डेशंस और व्यावहारिक सुधारों का सम्पूर्ण चित्र उभर सके। विशेष रूप से, पेपर तीन घटकों पर केंद्रित है: (1) वित्तीय परिरक्षण — लाभप्रदता, ROA/ROE, तरलता; (2) अनुपालन एवं प्रशासनिक लागत; और (3) बाजार पहुँच एवं प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति। समीक्षा से स्पष्ट होता है कि GST ने दीर्घकालिक रूप से कर-संगठन और राजस्व-प्रशासन में समन्वय लाने में योगदान दिया परंतु छोटे उद्यमों के लिए शुरुआती चरण में तकनीकी व नकदी चुनौतियाँ सामने आईं, जिनके लिए लक्ष्य-युक्त छूट, आसान रिटर्न, और नकद-आधारित अनुपालन विकल्प उपयोगी सिद्ध हुए हैं। अंततः यह शोध नीति-निर्माताओं के लिए सिफारिशें देता है — जैसे कि छोटे करदाताओं के लिए सरल रिटर्न मॉड्यूल, समय पर इनपुट-क्रेडिट विवाद निवारण प्रणाली, और लक्षित वित्तीय सुविधा। (मुख्य स्रोत: World Bank, Ministry of MSME, विविध शैक्षणिक अध्ययन और नीति-रिपोर्टें)।

Keywords: वस्तु एवं सेवा कर (GST), लघु उद्योग (MSMEs), अनुपालन लागत, नकद प्रवाह, इनपुट-क्रेडिट, वित्तीय सुदृढ़ता, भारत, नीति-सिफारिशें

Introduction

- वित्तीय व नीतिगत पृष्ठभूमि:** वस्तु एवं सेवा कर (GST) - 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया - का मूल लक्ष्य देश के जटिल अप्रत्यक्ष कर ढाँचे (कई स्तरों पर VAT, सीज शुल्क, सेवा कर इत्यादि) को स्थानिक तथा प्रक्रिया-गत एकीकृत कर तंत्र में बदलना था। GST ने कर-घर्षण (tax cascading) को कम कर इनपुट-क्रेडिट के समेकन के मार्ग खोल दिये, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार-एकीकृत होने और आंतरिक बाजार के सुसंगठित होने की उम्मीद थी। विश्व बैंक के विश्लेषण में भी भारत के GST के बदलावों को ऐतिहासिक और जटिल माना गया — जहाँ कई लाभ अपेक्षित थे परन्तु अनेक कार्यान्वयन-संबंधी चुनौतियाँ भी रहीं।^[1]
- लघु उद्योगों (MSMEs) की भूमिका:** भारत में MSMEs राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड हैं: वे रोजगार सृजन, निर्यात और ग्रामीण-शहरी आर्थिक समावेशन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, MSME क्षेत्र ने जीडीपी और रोजगार में बड़ी हिस्सेदारी दी है तथा विनिर्माण एवं सेवाओं दोनों में बड़ी उपस्थिति दर्ज करायी है। M/o MSME

की वार्षिक रिपोर्टें इस क्षेत्र की विविधता, वित्त-पोषण की आवश्यकताएँ और पॉलिसी-माध्यमों की संवेदनशीलता को स्पष्ट करती हैं।^[2]

- समस्याओं का स्वरूप — GST और छोटे उद्यमों का टकराव:** लघु उद्योग GST के प्रभावों के संदर्भ में कुछ विशेष संवेदनाएँ रखते हैं: (क) डिजिटल-आधारित अनुपालन की आवश्यकता - ऑनलाइन इनवॉइस, जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न फाइलिंग; (ख) इनपुट-क्रेडिट का त्वरित एवं निष्पक्ष निपटान; (ग) दर-श्रेणियों व सीमाओं का प्रभाव — (उदाहरण: 5%, 12%, 18%, 28% की बहु-स्तरीय दर संरचना); (घ) नकदी और फाइनेंसिंग — आउटसोर्सड इनवॉइस पेमेंट और देरी से भुगतान; तथा (ङ) रजिस्ट्री और रिपोर्टिंग खर्च। इन शर्तों के कारण छोटे उद्यमों को प्रारंभिक चरण में लागत-भार और परिचालन जटिलता का सामना करना पड़ा और कुछ मामलों में लघु निर्यात इकाइयों तथा परंपरागत घरेलू कारीगरों की प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई। अनेक शोध-पत्रों, नीति-विश्लेषणों और समाचार विश्लेषणों ने GST के प्रारंभिक आयामों और उसके बाद के सुद्वीकरणों पर चर्चा की है।^[3]

4. अनुसंधान प्रश्न:

यह समीक्षा निम्न प्रमुख प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करती है:

- GST ने लघु उद्योगों की वित्तीय स्थिति — लाभप्रदता, तरलता, ऋण-भुगतान क्षमता — पर क्या प्रभाव डाला?
- किस प्रकार के लघु उद्यम (उद्योग-आधारित, सेवाएँ, निर्यातक, घरेलू) पर प्रभाव भिन्न रहे?
- अनुपालन लागत और प्रशासनिक बाधाओं ने किस हद तक छोटे उद्यमों की परिचालन क्षमता प्रभावित की?
- सरकार द्वारा उठाये गए उपाय (जैसे Composition Scheme, threshold exemptions, सरल रिटर्न) कितने प्रभावी रहे, और आगे क्या सुधार सुझाये जा सकते हैं?

5. **विधिक-नीतिगत परिवेश:** GST Council द्वारा समय-समय पर दर समायोजन, Composition Scheme का विस्तार, e-invoicing का चरणबद्ध क्रियान्वयन एवं Threshold adjustments की घोषणाएँ सरकार द्वारा छोटे करदाताओं के बोझ को कम करने की दिशा में उठाए गए कदम रहे। तथापि, इन नीतियों का प्रभाव-विश्लेषण—विशेषकर वित्तीय सूचकांकों पर—अधिक व्यवस्थित एवं दीर्घकालिक विश्लेषण की मांग करता है। World Bank और अन्य संस्थाएँ भी GST के लम्बी अवधि के प्रभावों एवं प्रशासनिक चुनौतियों का उल्लेख करती हैं^[4]।

6. **पद्धति और सीमाएँ:** यह पेपर प्राथमिक डेटा संग्रह (अनुसंधान प्रश्नावली/सर्वे) पर निर्भर नहीं है; बल्कि यह द्वितीयक साहित्य, सरकारी रिपोर्ट, विश्व बैंक व शैक्षणिक जर्नलों (2017–2025) के समेकित विश्लेषण पर आधारित है। सीमा यह है कि कुछ नवीनतम आँकड़े राज्य-स्तर पर भिन्न हो सकते हैं और COVID-19 के बादलिखित आर्थिक परिवर्तनों के साथ GST के प्रभावों का पृथक्करण कठिन है। तथापि, बहु-स्तरीय स्रोत (सरकारी रिपोर्ट, विश्वबैंक विश्लेषण, शैक्षणिक लेख, और समेकित समीक्षाएँ) का उपयोग करते हुए, पेपर ने प्रभावों के ट्रेंड, कारण और नीतिगत इम्प्लीकेशनों को विवेचित किया है।

7. ऐतिहासिक प्रासंगिकता और कर-सुधार की पृष्ठभूमि

a) कर-ऐतिहासिकता का विकास (Pre-GST Tax Regime)

भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली GST लागू होने से पहले कई टायरों में विभाजित थी — जैसे राज्य स्तरीय VAT (Value Added Tax), केंद्र और राज्य द्वारा अलग-अलग लगाए जाने वाले सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, मनोरंजन कर आदि। यह जटिल ढांचा कई स्तरों पर कर-कास्केडिंग (tax cascading) का कारण बनता था — अर्थात् करों पर कर लगता था, जिससे उत्पाद लागत बढ़ती थी और व्यवसायिक निर्णयों पर विपरीत प्रभाव पड़ता था। मॉडिफाई (MODVAT) से लेकर VAT तक के क्रमिक सुधारों के बावजूद अप्रतिभेदित कर बुनियादी ढांचे ने व्यापार को बाधित किया और कर अनुपालन की लागत उच्च बनी रही^[5]।

b) प्रादेशिक VAT से GST की आवश्यकता

इस पृष्ठभूमि में GST की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि एकल, सर्व-भारत स्तर पर लागू कर प्रणाली से कर संगठनों के बीच टकराव कम होता, माल

और सेवाओं की इंटर-स्टेट मूवमेंट में बाधाएँ घटती, और “एक देश — एक बाजार” की अवधारणा सुदृढ़ होती। इससे व्यापारिक निर्णयों की पूर्वांशुमान क्षमता बढ़ती और व्यवसाय की लागत घटती। कई दशकों के अध्ययनों के परिणामस्वरूप आर्थिक एवं वित्तीय आयोगों ने सुझाव दिया कि समेकित अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से कर-आधार विस्तृत होगा तथा कर बुनियादी ढांचे के बीच समन्वय आएगा। भारत ने 1 जुलाई 2017 को GST लागू कर भू-राजस्व, VAT और सेवा कर जैसे कई अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया और ‘उत्पत्ति (destination-based)’ कर को अपनाया - अर्थात् कर उस राज्य में वसूला जाता है जहाँ वस्तु/सेवा का उपभोग होता है, न कि जहाँ उत्पाद का उत्पादन हुआ। यह बदलाव रणनीतिक दृष्टि से अर्थव्यवस्था को और अधिक सार्वभौमिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है^[6, 7]।

c) अपेक्षित अर्थशास्त्रीय लाभ

GST से अपेक्षित लाभों में प्रमुख हैं:

- **कर-कास्केडिंग प्रभाव में कमी:** कई स्तरों पर एक साथ लागू कर की जगह एकल GST से उत्पाद/सेवा की अंतिम लागत में कमी आती है और व्यापार संरचना में सुगमता बढ़ती है।
- **एकीकृत राष्ट्रीय बाजार:** राज्यों में अलग-अलग VAT की जगह GST ने पूरे देश को एक आम बाजार के रूप में जोड़ा, जिससे स्टॉक एवं इन्वेंटरी प्रबंधन बेहतर हुआ।
- **व्यापार में पारदर्शिता और जीएसटी-नेटवर्क (GSTN) आधारित डिजिटल प्रणाली:** कर अनुपालन डेटा के केंद्रीकरण से कर चोरी कम होती है और कर प्रशासन सुधरता है।
- **अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता:** बेहतर कर ढांचा विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकता है और निर्यातकों को इंटी-लेवल प्रतिस्पर्धा में फायदा देता है।

विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय निगरानी संस्थानों के विश्लेषण ने भी यह संकेत दिया है कि GST से भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में सकारात्मक प्रभाव संभावित है, जिससे निकासी-लागत कम होती है और समग्र GDP वृद्धि में योगदान होता है^[8]।

8. GST के तात्कालिक आर्थिक संकेतक और MSME प्रदर्शन

ROA, NET PROFIT MARGIN, CASH CONVERSION CYCLE

लघु उद्योगों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते समय कई वित्तीय संकेतक महत्वपूर्ण हैं:

- **ROA (Return on Assets):** कुल उपलब्ध संसाधनों पर लाभप्राप्ति सूचकांक एक प्रभावी कर ढांचे से संपत्ति-उपयोग दक्षता में सुधार होता है क्योंकि अप्रत्यक्ष कर बोझ की असंगति कम होती है।
- **नेट प्रॉफिट मार्जिन:** GST से इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने तथा कर-कास्केडिंग हटने पर कई इकाइयों के लिए सकल मार्जिन में वृद्धि के संकेत मिले हैं, विशेषकर उन उद्योगों में जो पूर्व में उच्च VAT/सेवा कर का बोझ उठाते थे।
- **कैश कन्वर्जन साइकिल:** GST के दौरान इनवॉइस-मैचिंग और इनपुट-क्रेडिट निपटान में देरी ने कुछ MSMEs में नकद प्रवाह-चक्र को विस्तारित किया — यानी उन्हें आपूर्तिकर्ताओं को जल्दी भुगतान करना पड़ता था जबकि इनपुट-क्रेडिट देरी से मिलता था, जिससे कार्यशील पूँजी पर दबाव पड़ा।

इन्वेन्टरी टर्न और बैंकों के क्रेडिट-डिफॉल्ट रेट

- **इन्वेन्टरी टर्न:** सही राष्ट्रीय कर ढांचे से राज्यों के बीच माल के लेन-देन में सुगमता से इन्वेन्टरी टर्न (स्टॉक रिसाइकलिंग) में सुधार होता है, जिससे भंडारण लागत घटती और पूंजी चक्र बेहतर होता है।
- **क्रेडिट-डिफॉल्ट रेट:** कुछ बैंकिंग रिपोर्टों में देखा गया कि GST लागू होने के बाद MSME सेन्सिटिव लोन सेक्टर में नकद-प्रवाह के त्वरित संघटन की कमी से कुछ इकाइयों ने डिफॉल्ट देखा, लेकिन सुधारों और प्रोत्साहनों के माध्यम से यह दबाव कम हुआ है।

MSME Ministry रिपोर्ट संकेत

भारत की MSME Ministry की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, GST लागू होने के बाद छोटे उद्यमों की राजस्व रिपोर्टिंग, कर अनुपालन और कारोबारी आंकड़ों की पारदर्शिता में सुधार हुआ, लेकिन प्रारम्भिक चरण में ऑटोमेशन, डिजिटल साक्षरता और इनपुट टैक्स क्रेडिट के समयबद्ध प्रमाणन प्रोसेस से नकदी-बोझ प्रभावित हुआ। यही वह आर्थिक संकेतक हैं जिन्हें शोध में वित्तीय प्रदर्शन के रूप में मापा गया। (M/o MSME Annual Reports, 2022–24) ^[9]

9. लघु उद्योगों के जोखिम और संवेदनाएँ

डिजिटल साक्षरता और वित्तीय व्यवहार

GST लागू होने के बाद MSME को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिटर्न और इनवॉइस संभालने की आवश्यकता पड़ी। यह डिजिटल साक्षरता का जोखिम बन गया — कई छोटे उद्यमों के पास IT संसाधन और प्रशिक्षण नहीं था, जिससे त्रुटियाँ, विलम्ब और अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता महसूस हुई। इससे नकदी-प्रवाह और प्रशासनिक लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ^[10]

लेन-देन की प्रकृति और सप्लाई चेन संबंध

- छोटे परंपरागत व्यवसायों में लेन-देन अक्सर नकद आधारित और अनौपचारिक होता है। GST की डिजिटल रिपोर्टिंग और निर्धारित इनवॉइस-प्रक्रिया से उत्पन्न बदलाव ने इन इकाइयों को अनुकूलन चुनौती से जूझना पड़ा।
- **आउटसोर्सिड सप्लाई चेन:** यदि एक MSME की इनवॉइसिंग/इनपुट-क्रेडिट प्रक्रिया उसकी सप्लाई चेन के बड़े भागीदारों पर निर्भर थी, तो देरी से प्रमाणन मिलने से व्यवसायिक नकद-प्रवाह पर दीर्घकालिक दबाव बन सकता है।
- **सीजनल उत्पादन:** जो उद्योग मौसमी उत्पादन/बिक्री करते हैं, उन्हें टैक्स रिटर्न चक्र में कमी-अधिकता के बीच अपने नकदी-चक्र योजना में ध्यान देना पड़ा है, जो एक संवेदनशील वित्तीय चुनौती बनता है।

इन जोखिमों और संवेदनाओं का वर्णन अनेक जर्नल-आर्टिकल्स और केस-स्टडी में किया गया है, जहाँ डिजिटल एडाप्शन, व्यवहारिक वित्त (behavioural finance) और छोटा व्यापार समर्थन संरचना की अत्यावश्यकता पर बल दिया गया है।

10. नीतिगत प्रतिक्रियाएँ और उनका प्रभाव

Composition Scheme

GST Council ने छोटे करदाताओं के लिए Composition Scheme लागू किया - जिसमें सीमित आवंटन पर साधारण रेट देय होता है और जटिल रिटर्न-

फाइलिंग की आवश्यकता कम होती है। इससे बहुत-से छोटे उद्यमों के लिए अनुपालन-बोझ घटा है और नकद-प्रवाह में स्थिरता आई है। Composition scheme के अंतर्गत MSMEs अपने व्यवसाय के प्रकार के अनुसार एक सरल प्रतिशत रेट पर कर का भुगतान करते हैं, जिससे छोटे उद्यमों के लिए लाइबिलिटी और अनुपालन सरल हो जाता है ^[11]।

Threshold Exemptions

GST में **threshold exemptions** (जैसे ₹40 लाख तक की वार्षिक टर्नओवर पर कर-रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं) ने बहुत-से सूक्ष्म उद्यमों को प्रारम्भिक कॉम्प्लायंस बोझ से मुक्त किया, जिससे उन्हें अपनी फोकस रणनीतियों, उत्पादन और विपणन पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिली ^[12]।

e-invoicing और रिटर्न संदर्भ

GST प्रशासन ने डिजिटल विधियों - जैसे E-invoicing, QR-B2B इनवॉइस मॉचिंग और निरंतर कम संख्यक रिटर्न फॉर्म - के माध्यम से अनुपालन को सुसंगठित किया है। यह डिजिटल संरचना कुछ MSMEs के लिए सरलता लाती है; पर दूसरी ओर कई इकाइयों को उसकी शुरुआत में तकनीकी लागत और प्रशिक्षण-समर्थन की आवश्यकता पड़ी। इस डिजिटल परिवर्तित ढांचे ने कर प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाई और कर चोरी कम की है ^[13]।

सरकार और विश्व बैंक के सुधार सुझाव

विश्व बैंक और नीति-विश्लेषणों ने GST व्यवस्था में सरल दर स्लैब, बेहतर इनपुट टैक्स क्रेडिट त्वरित निपटान प्रक्रिया, और डिजिटल सहायता कार्यक्रम की सिफारिश की है ताकि छोटे उद्यमों के लिए वित्तीय बोझ और अनुपालन-चुनौतियों को और अधिक कम किया जा सके ^[14]।

साहित्य समीक्षा

1. **Franco & Chellammal (2018)** — GST के प्रारम्भिक चरणों में छोटे उद्योगों पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव दोनों का उल्लेख; विशेषकर कंप्लायंस लागत की बढ़त और कर-मुक्तिकरण से formalisation में सहायता।
2. **Nayyar & Singh (2018)** - व्यापक विश्लेषण: GST ने कर-त्रुटि घटाई पर बहु-रेट संरचना तथा प्रशासनिक जटिलताओं की वजह से छोटे करदाताओं को प्राथमिक रूप से अधिक बोझ उठाना पड़ा।
3. **Murari & Chettri (2020)** - राज्य-स्तरीय अध्ययन (Sikkim): MSMEs ने GST को विकास के अवसर के रूप में देखा परन्तु प्रारम्भिक तरलता-संकट और इनवॉइस-मैचिंग की समस्याएँ सामने आईं।
4. **Deshmukh, Mohan & Mohan (2022)** - SAP-LAP-Twitter विश्लेषण के माध्यम से GST के कार्यान्वयन पर सामाजिक-सांकेतिक संकेतों का अध्ययन; इसने क्रियान्वयन-संबंधी शिकायतों और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित किया।
5. **World Bank (Multiple papers, 2017–2024)** - भारत के GST पर व्यापक नीति-पत्र: लाभ (एकीकृत आंतरिक बाजार, कमी ऑन टैक्स-कास्केडिंग) एवं चुनौतियाँ (बहु-रेट, कंप्लायंस लागत, आईटी सिस्टम) को इंगित किया। यह वैश्विक तुलना और सुधारों के सुझाव देता है।

6. **Ministry of MSME - Annual Reports (2022–24)** - सरकारी आँकड़े: MSME पंजीकरण, क्रेडिट-पुलिंग, और GST-सम्बन्धी सहायता कार्यक्रमों का विवरण; नीति-प्रेरित कार्यक्रमों की सफलताओं और कमियों का चित्र प्रस्तुत किया गया।

7. **Systematic reviews / recent papers (2023–2025)** - विविध जर्नलों में प्रकाशित समीक्षाओं ने संकेत दिया कि GST ने दीर्घावधि में formalisation और बाज़ार-एकीकरण में योगदान दिया किंतु छोटे उद्यमों के लिए targeted उपाय आवश्यक हैं; कुछ अध्ययनों ने COVID-19 के बाद स्थिति को जटिल बताया।

उपरोक्त साहित्य से स्पष्ट होता है कि GST के आर्थिक व प्रशासनिक लाभ (कर-वृद्धि घटाना, वित्तीय पारदर्शिता, इनपुट-क्रेडिट) वास्तविक हैं, परन्तु छोटे उद्यमों के लिए प्रारम्भिक चरण में अनुपालन लागत, डिजिटल-डिवाइड और नकदी-संकट जैसे नकारात्मक प्रभावों की पुष्टि होती है। नीति-लेवल पर Composition Scheme, threshold वृद्धि और सरल रिटर्न जैसे उपायों ने आंशिक राहत दी, किन्तु त्वरित इनपुट-क्रेडिट समाधान और क्रेडिट-गैर-नवीनीकरण (delayed credit) से उत्पन्न नकदी-समस्याओं का दीर्घकालिक अध्ययन अपेक्षित है।

अध्ययन की रूपरेखा और पद्धति

यह शोध-पत्र एक सिस्टमैटिक-नैरेटिव समीक्षा (systematic narrative review) है - जिसका उद्देश्य 2017–2025 के बीच प्रकाशित प्राथमिक/द्वितीयक स्रोतों का समेकन एवं विश्लेषण करना है। पद्धति के मुख्य चरण निम्नानुसार रहे:

1. स्रोत चयन (Source selection):

- त्रुटिहीन स्रोतों के लिए खोज-शब्दों का प्रयोग: "GST impact MSME India", "GST effect small industries India", "MSME annual report 2023-24", "World Bank GST India" आदि।
- डेटाबेस व स्रोत: World Bank रिपोर्टें, M/o MSME वार्षिक रिपोर्टें, Google Scholar, ResearchGate, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जर्नल आर्टिकल्स, सरकारी प्रकाशन और प्रमुख समाचार संस्थान।

2. समावेश/बहिष्कार मानदण्ड (Inclusion/Exclusion criteria):

- समावेश: 2017–2025 के बीच प्रकाशित शोध-पत्र, नीति-रिपोर्ट, और आधिकारिक आँकड़े जो GST और MSME/लघु उद्योगों के बीच सम्बन्ध पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश डालते हों।
- बहिष्कार: GST से अप्रत्यक्ष रूप से असंबंधित लेख, अथवा सीमित/अनप्रासंगिक केस-स्टडी जिन्हें व्यापक निष्कर्षों में परिवर्तित नहीं किया जा सके।

3. डेटा-संग्रह और विश्लेषण (Data extraction & synthesis):

- प्रत्येक चुने गए स्रोत से प्रमुख बिंदु निकाले गए: वित्तीय संकेतक (profitability, liquidity), अनुपालन लागत, इनपुट-क्रेडिट समस्याएँ, नीति प्रतिक्रियाएँ और निहित समाधान।

- परिणामों को थीमेटिक रूप में व्यवस्थित किया गया: (a) वित्तीय प्रभाव; (b) अनुपालन एवं प्रशासनिक लागत; (c) बाज़ार व प्रतिस्पर्धा; (d) नीति-प्रभाव एवं सुधारा।

- जहाँ सम्भव था, सरकारी आँकड़ों के माध्यम से ट्रेड-आधारित तुलनात्मक तालिकाएँ तैयार की गयीं (उदाहरण: MSME पंजीकरण, क्रेडिट डिस्बर्सल) ^[15]।

4. विश्वसनीयता और सीमाएँ (Reliability & Limitations):

- द्वितीयक-डेटा पर आधारित होने के कारण यह अध्ययन causation की पक्की पुष्टि नहीं कर सकता; परन्तु यह व्यापक पैटर्न और नीतिगत संकेत प्रदान करता है।
- COVID-19 के बाद अर्थव्यवस्था में आये व्यवधानों के आवृत्ति-प्रभाव को अलग करना जटिल रहा, इसलिए परिणामों में सम्भावित कॉन्फाउंडिंग प्रभावों का उल्लेख किया गया है।

(A) विवरणात्मक विश्लेषण

1. वित्तीय संकेतक और GST के प्रभाव

- **लाभप्रदता (Profitability):** कुछ सेक्टरों में GST के बाद इनपुट-क्रेडिट उपलब्धता के कारण सकल मार्जिन में सुधार देखा गया; परन्तु छोटे विनिर्माण इकाइयों में प्रारम्भिक लागत-भार और डिजिटल-रिलेडेड निवेश के कारण स्वल्पावधि में लाभप्रति घटने की रिपोर्टें मिलीं। (उदाहरण: MSME Annual Reports में संकेत) ^[16]।
- **तरलता (Liquidity) व नकद प्रवाह:** इनवॉइस-मैचिंग तथा Input Tax Credit (ITC) के भुगतान में देरी का प्रमुख परिणाम नकदी-संकुचन रहा — विशेषकर वे इकाइयाँ जो बड़े बायर/कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ काम करती हैं और जिन्हें भुगतान में देरी का सामना करना पड़ता है। सरकारी सहायता योजनाओं के बावजूद क्रेडिट-समस्या बनी रही ^[17]।

2. अनुपालन लागत और डिजिटल परिवर्तन

- GST ने रिटर्न-फाइलिंग, e-invoicing और इनवॉइस-मैचिंग जैसे डिजिटल प्रक्रियाओं को अनिवार्य कर दिया। छोटे उद्यमों के लिए यह तकनीकी तथा प्रशिक्षण-गत चुनौती साबित हुआ। कई अध्ययनों ने बताया कि प्रारम्भिक चरण में SMEs ने IT सिस्टम व कॉन्सल्टेंसी पर अतिरिक्त व्यय किया ^[18]।

3. विभिन्न प्रकार के लघु उद्यमों पर भिन्न प्रभाव

- **निर्यात-उन्मुख MSMEs:** कुछ अध्ययनों ने नोट किया कि GST के प्रारम्भिक चरण में निर्यात से संबंधित रिफंड प्रक्रियाओं व दस्तावेजी जटिलताओं के कारण निर्यातकों को अस्थायी व्यवधानों का सामना करना पड़ा, जिससे कुछ महीनों के लिए निर्यात-प्रवाह प्रभावित हुआ ^[19]।

- **घरेलू कारीगर और परम्परागत इकाइयाँ:** ये इकाइयाँ प्रायः डिजिटल साक्षरता व औपचारिक पंजीकरण में पिछड़ी हैं; GST ने आधिकारिक रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता से उनकी अनुपालन-सामर्थ्य पर दबाव डाला [20]।

4. नीति-उपायों का प्रभाव

- **Composition Scheme:** छोटे करदाताओं के लिए सरल रेजिमेन का परिचय दिया गया; इससे कुछ इकाइयों को अनुपालन-साधन प्राप्त हुए परन्तु

सीमाएँ (वस्तु प्रकार, सीमा-नियमन) बनी रहीं।

- **Threshold बढ़ोतरी व रेट-समायोजन:** GST Council की समय-समय पर की गई दर-समायोजनों ने कुछ वस्तुओं के लिए राहत दी; परन्तु बहु-रेट संरचना अभी भी जटिलता का स्रोत है।

(B) तालिका - उदाहरणात्मक

Table 1: GST-सम्बन्धी प्रमुख नीतिगत उपाय और लघु उद्योगों पर संभावित प्रभाव (सारांश)

नीति/उपाय	उद्देश्य	लघु उद्योगों पर संभावित प्रभाव
Composition Scheme (सरल कर)	अनुपालन सरल बनाना	छोटे करदाताओं के लिए रिटर्न बोझ घटता है; लेकिन बाजार-प्रतिस्पर्धा सीमित
Threshold exemptions	बहुत छोटे उद्यमों को बाहर रखना	अनुपालन लागत में कमी; पर अनौपचारिकता बनी रहती है
e-invoicing rollout (चरणबद्ध)	इनवॉइस-मिलान में पारदर्शिता	ITC प्रक्रिया सुधर सकती है; पर डिजिटल लागत बढ़ती है
रेट समायोजन (कई वस्तुओं में कटौती/वृद्धि)	कर-न्याय/राजस्व समायोजन	छोटे उपभोक्ता वस्तु निर्माताओं को लाभ; पर जटिलता बनी रहती है

*(स्रोत: GST Council घोषणाएँ, M/o MSME रिपोर्टें, World Bank विश्लेषण)।

(C) केस-उदाहरण और अनुभव

- **केस A — सूक्ष्म विनिर्माण इकाई (ग्राम स्तर):** प्रारम्भ में पंजीकरण व डिजिटल रिटर्न चुनौतीपूर्ण; स्थानीय कर सलाहकार पर निर्भरता; लेकिन 2 वर्षों में कीमत प्रतिस्पर्धा सुधार की सूचना। (स्रोत: स्थानीय केस-स्टडी/जर्नल रिपोर्टें)।
- **केस B — एक्सपोर्ट-अनुकूल MSME:** रिफंड विलंब के कारण Working Capital squeeze; बैंकिंग सहयोग व सरकारी रिफंड-प्रक्रिया में सुधार से स्थिति स्थिर हुई।

(D) नीतिगत सिफारिशें

- **सरल, किफायती और लक्षित अनुपालन-मॉड्यूल:** छोटे करदाताओं के लिए मोबाइल-आधारित आसान रिटर्न और न्यूनतम दस्तावेजीकरण। (स्रोत: MSME Annual Report suggestions)।
- **त्वरित ITC निपटान तंत्र:** इनपुट-क्रेडिट विवादों का संवेदनशील एवं तीव्र निपटान ताकि नकदी-संकट कम हो। (स्रोत: World Bank analysis)।
- **लक्ष्य-समर्थन वित्त (targeted credit line):** GST-आधारित अनुपालन लागत के लिए विशेष रिण-उपाय और तुरंत क्रेडिट गारंटी। (स्रोत: MSME policy reviews)।
- **डिजिटल साक्षरता एवं प्रशिक्षण:** क्षेत्रीय कैम्प, ऑनलाइन ट्यूटोरियल व सॉफ्टवेयर पहूँचा। (स्रोत: अनेक जर्नल अनुशांसाएँ)।

निष्कर्ष

1. GST ने भारत के अप्रत्यक्ष कर तंत्र में गहरा परिवर्तन लाया; दीर्घकालिक लाभ (कम कर-त्रुटि, बाजार-एकीकरण, पारदर्शिता) स्पष्ट हैं। लघु उद्योगों (MSMEs) पर प्रभाव मिश्रित रहा: लाभप्रदता व प्रतिस्पर्धात्मकता के कुछ संकेत मिले पर प्रारम्भिक चरण में अनुपालन-लागत व नकदी-संकट प्रमुख चुनौतियाँ रहीं।

2. नीति-निर्माताओं को इस मिश्रित प्रभाव को ध्यान में रखकर आदर्श रूप से “लक्ष्य-उन्मुख” और “चरणबद्ध” सुधार लागू करने चाहिए — जैसे कि Composition Scheme का समुचित विस्तार, रिफंड-सिस्टम में पारदर्शिता, और छोटे करदाताओं के लिए डिजिटल-सहायता।

3. अनुसंधान-गैप और भविष्य के शोध हेतु सुझाव:

- दीर्घकालिक, पैर-इंडिकेटर (ROA, ROE, CCC) आधारित औपचारिक अध्ययन की आवश्यकता।
- राज्य-स्तर पर GST के प्रभाव का तुलनात्मक विश्लेषण (क्योंकि अनुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर व राज्य-नीतियाँ भिन्न हैं)।
- COVID-19 के बाद MFIs, बैंकिंग और GST के अंतर्संबंध पर विस्तृत causal-पाठ्यक्रम।

4. **नैतिक व सामाजिक विचार:** छोटे उद्यमों के सामाजिक-आर्थिक संदर्भ (रोजगार, ग्रामीण विकास) को दृष्टि में रखकर नीति-निर्माण किया जाना चाहिए ताकि संकुचित पूँजी तक पहुँच व अनुपालन बोझ सामाजिक असमानताएँ न बढ़ाये।

संदर्भ

1. Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Government of India. MSME annual report 2023–24 [Internet]. New Delhi: Government of India; 2024 [cited 2026 Feb 27]. Available from: <https://msme.gov.in>
2. Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Government of India. MSME annual report 2022–23 [Internet]. New Delhi: Government of India; 2022 [cited 2026 Feb 27]. Available from: <https://msme.gov.in>
3. World Bank. Implementation of India’s goods and services tax (GST) [Internet]. Washington (DC): World Bank; 2019 [cited 2026 Feb 27]. Available from: <https://documents1.worldbank.org>

4. World Bank. The challenges of the goods and services tax (GST) implementation in India. Washington (DC): World Bank; 2019.
5. Kohli R. India's GST reform: Policy perspectives. 2025.
6. The impact of GST on Indian businesses: A comprehensive review. 2024. Available from: ResearchGate.
7. Adesh M. Analyzing the impact of GST on small and medium enterprises. 2025.
8. Murari K, Chettri S. Perceived impact of goods and services tax (GST) and growth of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Sikkim. Orissa J Commer. 2020;41(2):97–116.
9. Deshmukh AK, Mohan A, Mohan I. Goods and services tax (GST) implementation in India: A SAP–LAP–Twitter analytic perspective. Glob J Flex Syst Manag. 2022;23(2):165–183.
10. Economic Times; Systematix Research. GST cuts to boost economy, but revenue loss could hit banking sector [Internet]. 2025 [cited 2026 Feb 27].
11. Reporter's Collective. When Modi Govt, RBI told half-truths and lies to downplay damage to small businesses [Internet]. 2024 [cited 2026 Feb 27].
12. (अतिरिक्त संदर्भ — जर्नल एवं कन्फ्रेंस पेपर्स): अनेक छोटे अध्ययन (2018–2024) जिनमें Franco & Chellammal (2018), Chitra Suraj Ashtekar (2019), Anand Nayyar & Inderpal Singh (2018) आदि का समावेश है। (स्रोत संकलन: ResearchGate तथा J-Gate/Google Scholar)
13. World Bank Document
14. <https://msme.gov.in/sites/default/files/FINALMSMEANNUALREPORT2023-24ENGLISH.pdf>
15. The impact of GST (Goods and Services Tax) on Indian Businesses: A Comprehensive Review
16. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/3918c8c6930fae90360b34f6e6ad9744-0310022025/related/1-GST-Renu-Kohli-CSEP.pdf>
17. Goods and Services Tax (India) - Wikipedia
18. World Bank Document
19. Goods and Services Tax (India) - Wikipedia
20. India Development Update: Continue Domestic Reforms and Encourage Investments
21. FICCI.pdf
22. [ijrsonline.in/HTML_Papers/International Journal of Reviews and Research in Social Sciences __PID__ 2025-13-3-1.html](http://ijrsonline.in/HTML_Papers/International_Journal_of_Reviews_and_Research_in_Social_Sciences__PID__2025-13-3-1.html)
23. 150_1803_21.pdf
24. https://icmai.in/TaxationPortal/upload/IDT/Article_GST/150_1803_21.pdf
25. https://ijrsonline.in/HTML_Papers/International%20Journal%20of%20Reviews%20and%20Research%20in%20Social%20Sciences__PID__2025-13-3-1.html
26. India Development Update: Continue Domestic Reforms and Encourage Investments
27. <https://msme.gov.in/sites/default/files/FINALMSMEANNUALREPORT2023-24ENGLISH.pdf>
28. <https://msme.gov.in/sites/default/files/FINALMSMEANNUALREPORT2023-24ENGLISH.pdf>
29. When Modi Govt, RBI told half-truths and lies to downplay damage to small businesses
30. The Impact of GST (Goods and Services Tax) on Indian Businesses: A Comprehensive Review
31. When Modi Govt, RBI told half-truths and lies to downplay damage to small businesses
32. The Impact of GST (Goods and Services Tax) on Indian Businesses: A Comprehensive Review.